**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1665

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**विकलांग छात्रों पर व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना**

**1665. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः**

**श्रीमती अम्बिका सोनीः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान, विकलांग छात्रों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने वाले केन्द्रीय विद्यालयों, और केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों द्वारा अभिशासित विद्यालयों सहित विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध् में कोई आदेश जारी किए हैं; और

(ग) क्या सरकार की रोजगार के अवसरों के लिए विकलांग स्कूली बच्चों को कौशल-उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित केंद्रीय प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत, एक अहम घटक है जो सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत निशक्त छात्रों की शिक्षा हेतु विशिष्ट छात्र उन्‍मुखी हस्तक्षेपों जैसे बेल पुस्तकें/किट का प्रावधान, शिक्षण अधिगम सामग्री, वर्दी, परिवहन और एस्कॉर्ट भत्ता, पहचान और मूल्यांकन कैंप और सुधारात्मक उपाय करने आदि हेतु समर्पित है।

 तथापि, स्कूल द्वारा किए गए व्‍यय के विरुद्ध प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा निशक्त छात्रों पर किए गए व्‍यय के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं है। नवोदय विद्यालय संगठन (एनवीएस) स्कूलों के तहत, स्कूलों में भोजन और आवास सहित निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। केंद्रीय तिब्‍बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) भी भारत में निशक्त बच्चों सहित तिब्‍बजी शरणार्थी बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है।

(ग): समग्र शिक्षा योजना में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों हेतु व्यावसायिक शिक्षा का एक घटक है। नियमित स्कूलों में अध्‍ययन कर रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्‍ल्‍यूएसएन) अपनी क्षमता और नि:शक्‍तता स्थिति के अनुसार योजना के तहत उपलब्ध 17 ट्रेडों जैसे सुंदरता और स्वास्थ्य, रिटेल, आईटी और हेल्थकेयर आदि से कोई ट्रेड चुन सकते हैं। सीडब्‍ल्‍यूएसएन के लिए विशेष रूप से कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने की कोई अलग योजना नहीं है।

**\*\*\*\*\***